



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032020-218834  
CG-DL-E-21032020-218834

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1060]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2020/फाल्गुन 30, 1941
No. 1060]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2020/PHALGUNA 30, 1941

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2020

**का.आ. 1188(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग), (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 1537(अ) दिनांक 09 अप्रैल, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में-

(क). तीसरे अनुच्छेद के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2011-12 में 01.06.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के लिए और कर निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 के लिए भी लागू माना गया है और कर निर्धारण वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के संबंध में लागू होगा”

(ख). अंत में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण ज्ञापन अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

**“स्पष्टीकरण ज्ञापन**

मैसूर पैलेस बोर्ड v में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर इस अधिसूचना को कर निर्धारण वर्ष 2011-12 में 01.06.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के लिए और कर निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 के लिए भी भूतलक्षी प्रभाव दिया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं तीन अन्य ने दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 की रिट याचिका संख्या 2019 की 40801 में यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा”।

3. यह अधिसूचना 9 अप्रैल, 2019 से लागू मानी गई है।

(अधिसूचना सं. 19/2020 फा. सं. 300196/63/2018-आईटीए-1)

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

**स्पष्टीकरण ज्ञापन**

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को 09 अप्रैल, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव देने पर किसी व्यक्ति के हित पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**नोट:** प्रधान अधिसूचना को दिनांक 09 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना सं. का. आ.1537 (अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (II) में प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)**

(Central Board of Direct Taxes)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th March, 2020

**S.O. 1188(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue), (Central Board of Direct Taxes) number S.O.1537(E) dated 09<sup>th</sup> April, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

2. In the said notification,-

(a) for the third paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“3. This notification shall be deemed to have been applied for the period from 01-06-2011 to 31-03-2012 in the assessment year of 2012-2013 and also from the assessment years 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 and shall apply with respect to the assessment years 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, and 2023-2024.”;

(b) at the end, the following Explanatory Memorandum shall be inserted, namely:-

**“Explanatory Memorandum**

This notification shall be given retrospective effect for the period from 01-06-2011 to 31-03-2012 in the assessment year of 2012-2013 and also from the assessment years 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, in view of the order of the Hon'ble High Court of Karnataka in the matter of Mysore Palace Board V. the Central Board of Direct Taxes and 3 Others [W.P. No.40801 of 2019 (T-IT)], dated 17<sup>th</sup> Day of December, 2019. It is certified that by giving retrospective effect to the notification no person interest will adversely get affected.”.

3. This notification shall be deemed to have come into effect from 09<sup>th</sup> April, 2019.

[Notification No. 19/2020/ F.No.300196/63/2018-ITA-I]

PRAJNA PARAMITA, Director

**Explanatory Memorandum**

It is hereby certified that no person interest is adversely affected by giving retrospective effect to this notification from 9<sup>th</sup> April, 2019.

**Note:** The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (II) vide No. S.O. 1537(E) dated the 09<sup>th</sup> April, 2019.